to task but not the officers;

(c) if so, whether such officers have been sent out on foreign postings to avoid legal action; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) and (b) Life Insurance Corporation (LIC) have reported that after investigating the complaints received, they would initiate such action as deemed necessary in case any officer is found guilty. The LIC have confirmed that no officer can avoid legal action simply because he has been posted on a foreign assignment in case he is found guilty. In case of a few Agents who had not fulfilled the prescribed norms, already Club-Membership discontinuation letters had been sent.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रिलायंस औद्योगिक समूह में किया गया निवेश

2227. **श्री संजय गौतम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रिलायंस औद्योगिक समूह में कुल कितना-कितना निवेश किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन दोनों वित्तीय संस्थाओं की इस समूह में वित्तीय धारिता कितनी-कितनी है;

(ग) क्या उक्त औद्योगिक समूह द्वारा वित्तीय लेन-देन में भारी पैमाने पर अनेक अनियमितताएं बरती गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पॉल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Package of Regional Rural Banks available to Rural Branches of Commercial Banks

2228. SHRI Z RAMCHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether package of measures recently applicable of Regional Rural Banks are also available to rural branches of Commercial Banks since inception;

(b) whether a number of rual branches of Commercial Banks are running with losses inspite of such facilities;

(c) steps taken by Government to select Tripura Gramin Bank for restructuring; and

(d) by when it is expected to be selected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) The Regional Rural Banks (RRBs) have been allowed to undertake non-fund business as part of a package introduced for strengthening them. These facilities were already available in the branches of commercial banks including rural branches since inception. Besides, RRBs have been allowed to give credit to non-target groups upto 60% of the fresh lending. The commercial banks were already allowed to give credit upto 60% to such groups.

(b) As reported by Reserve Bank of India (RBI), some rural branches of commercial banks are running into losses.

(c) and (d) Tripura Gramin Bank was among 50 RRBs recommended by a Committee set up by RBI for the purpose of restructuring of RRBs during 1994-95. This bank, however, has not been taken up for restructuring through infusion of equity so far due to its very weak financial position and huge losses. A separate study has been made by a team

constituted by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). The selection of Tripura Gramin Bank for restructuring is contigent on the finalisation of a suitable package of measures having regard to its special problems.

Proposal for assistance from ADB to Royalseema Thermal Power Station

2229. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have received a request from Government of Andhra Pradesh to forward the Royalseema Thermal Power Station Stage III for external assistance to the Asian Development Bank;

(b) if so, whether the APB had been approached; and

(c) the status of this request at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) There is no proposal for installation of Royalseema Thermal Power Station Stage-III.

पर्यटक विभाग के विदेशी कार्यालय की उपलब्धियां

2230. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पर्यटन विकास के विदेशों में कार्यरत कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों की क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या इनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे कुछ और नए कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कार्यालय कहां-कहां खोले जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस समय भारत सरकार के 18 पर्यटक कार्यालय विदेश में कार्य कर रहे हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के सम्मिलित प्रयासों के कारण, गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों और विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिशत वृद्धि सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और विदेशी मुद्रा अर्जन को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ङ) और (च) पर्यटन विभाग के मास्को, तेल अवीव, जोहन्सबर्ग, सियोल और दक्षिण अमरीका में कुछ नए कार्यालय खोलने के प्रस्ताव हैं।

विवरण I

विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों की सूची

क्रम सं०	कार्यालय का नाम
1.	न्यूयार्क
2.	लास ऐंजिल्स
3.	टोरोंटो
4.	लंदन
5.	जैनेवा
6.	मेड्रीड
7.	पैरीस
8.	फ्रैंकफर्ट
9.	स्टोकहोम
10	एमस्टर्डेम
11.	मिलान
12.	दुबई
13.	बैहरीन
14.	सिडनी
15.	टोक्यो
16.	सिंगापुर
17.	कुआलालमपुर
18.	बैंकाक